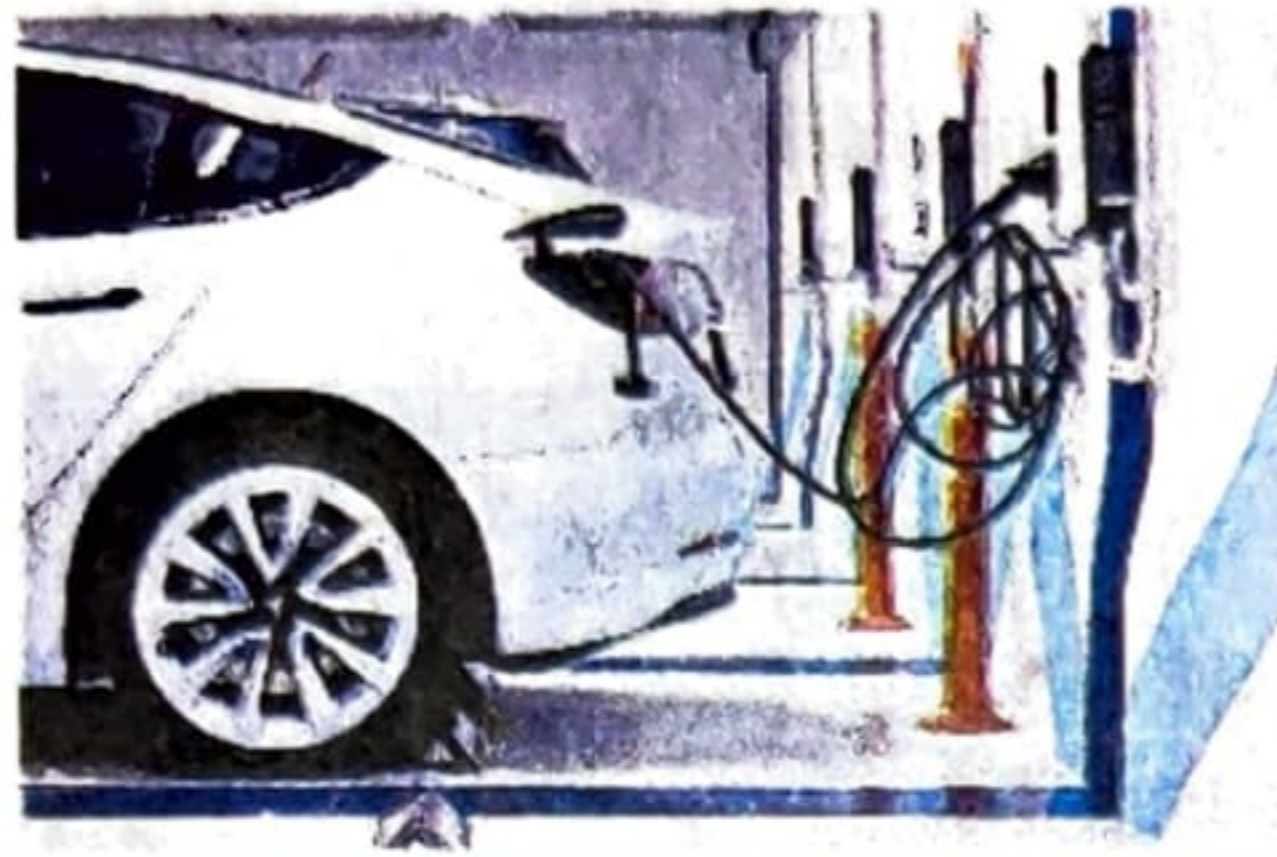


# ईवी नीति में आयात शुल्क में कटौती संभव

नई दिल्ली, रायटर: केंद्र सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति पर काम कर रही है। इस नीति में घरेलू मैनुफैक्चरिंग का वादा करने वाले वाहन निर्माताओं के लिए आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिका की दिग्गज ईवी निर्माता टेस्ला के प्रस्ताव के बाद सरकार आयात शुल्क में कटौती पर विचार कर रही है।

सूत्रों का कहना है कि नई ईवी नीति में वाहन निर्माताओं को 15 प्रतिशत शुल्क पर पूरी तरह से निर्मित ईवी आयात करने की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। अभी 40 हजार डालर से ज्यादा मूल्य की कारों के आयात पर 100 प्रतिशत और इससे कम मूल्य की कारों के आयात पर 70 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। टेस्ला के सबसे ज्यादा बिकने वाले माडल वाई का मूल्य अमेरिका में 47,740 डालर से शुरू होता है। इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया कि टेस्ला के प्रस्ताव पर सहमति बनती दिख रही है और सरकार इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। इस संबंध



- पूरी तरह से निर्मित ईवी को 15% शुल्क पर आयात की छूट संभव
- अभी 40 हजार डालर से ज्यादा की कार के आयात पर है 100% शुल्क

## आयातित ईवी की लागत में होगी बड़ी कटौती

सूत्रों का कहना है कि यदि ऐसी नीति अपनाई जाती है तो इससे आयातित ईवी की लागत में भारी कमी आ सकती है। यह कदम टेस्ला के अलावा अन्य वैश्विक वाहन निर्माताओं के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े

में वाणिज्य मंत्रालय और टेस्ला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उधर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईवी के आयात शुल्क में कटौती को लेकर उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिकारी ने कहा कि सरकार

शुल्क में कटौती से बाधित हो सकता है घरेलू बाजार

एक अधिकारी ने कहा कि सरकार नई नीति पर विचार करने में धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि आयातित ईवी पर शुल्क कम करने से घरेलू बाजार बाधित हो सकता है। नई नीति से टाटा और महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां परेशान हो सकती हैं। यह कंपनियां ईवी मैनुफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं।

कार बाजार में प्रवेश का द्वार भी खोल सकता है। सूत्र का कहना है कि कम आयात शुल्क से टेस्ला को भारत में अपने सभी माडल बेचने में मदद मिल सकती है, न कि केवल नई कार जिसे वह स्थानीय स्तर पर बनाना चाहती है।

भले ही टेस्ला को भारत लाने की इच्छुक है, लेकिन आयात शुल्क में कटौती के प्रस्ताव पर काफी विचार-विमर्श किया जाएगा। नई नीति अभी प्रारंभिक चरण में है और शुल्क की अंतिम दर बदल सकती है।